

## स्वच्छता अभियान : एक आत्ममन्थन

### सारांश

लोकसभा 2014 के आम चुनाव अभियान में चारों तरफ 'अहम श्रेष्ठ अस्मि अहम श्रेष्ठ अस्मि' का शंखनाद हो रहा था। इस चहल पहल के वातावरण में भाजपा प्रमुख श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को अपने चुनाव घोषणा पत्र का आधार स्तम्भ बनाया। स्वच्छ भारत की सोच को आगे बढ़ाकर भारतीय जनमानस में उतरने का प्रयास प्रारम्भ हुआ। महिला सुरक्षा व गरिमा का मुद्दा, रोजागार, मंहगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, शारीरिक मानसिक विकास, निरोगी वातावरण, स्वच्छता सेवा जैसे संवेदनशील आवश्यकताओं के जरिए स्वयं को जनता से जोड़ा।

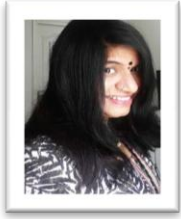
**मुख्य शब्द** : श्रेष्ठ, घोषणापत्र, गरिमा, मुद्दा, गौरवान्वित, जनमानस।

### प्रस्तावना

स्वच्छता शब्द ही इतना सारगर्भित है कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने-अपने स्तर और आवश्यकताओं पर इसे समझा तथा अपने-अपने स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी मानी। जहां निम्न स्तर के लोग खुले में शौच का विरोध करने लगे तथा कूड़े और अपशिष्ट पदार्थों को इधर-उधर फेंकने से बचने लगे वही उच्चस्तरीय लोग शौचालय निर्माण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में टी0वी0, रेडियो, दूरदर्शन तथा आउटडोर होर्डिंग के माध्यम से 'दरवाजा बंद' अभियान चलाया। हाल ही में बालीबुड ने 'टाइलेट-एक प्रेमकथा' नाम की एक फिल्म भी बनाई जिसने सामान्य जनता के मन-मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डाला।

### अध्ययन का उद्देश्य

इस लेख को लिखने का मेरा उद्देश्य हमारे भारतीय जनमानस को स्वच्छता के प्रति चेतना जाग्रत करने का प्रयास है तथा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी जी के स्वच्छता संकल्प अभियान में अपनी लेखनी के माध्यम से चेतना जाग्रत करने का एक छोटा सा प्रयास है।



**मीनाक्षी शर्मा**

एसोसिएट प्रोफेसर,  
राजनीति विज्ञान विभाग,  
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स  
कालेज,  
मुरादाबाद



‘स्वच्छता’ शब्द का प्रारम्भ एक राजनैतिक माहौल में हुआ परन्तु सामाजिक स्तर पर लोगों ने इसे आत्मसात किया। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना तो जरूरी है ही पर इससे भी बड़ा कार्य है, स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलना।

इसके लिए ‘स्वच्छता’ को केवल सरकार था सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं मानकर सभी की जिम्मेदारी बनाना होगा तथा एक जन आन्दोलन का रूप देना होगा। स्वच्छता को लोगो के आत्ममंथन का विषय बनाना होगा। जिस प्रकार आज के समय में जन्म से ही माता-पिता बालक बालिकाओं के शिक्षा पर विचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कम से अपने बच्चो के आस-पास के वातावरण को स्वच्छ बनाने और स्वच्छता की आदत डालने के बारे में भी विचार करना चाहिए। कुछ हालिया पहल यह साबित करती है, कि प्रधानमंत्री का विजन एस0बी0एम0 एक जन-आंदोलन में बदल रहा है। 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2017 तक चले अभियान ‘स्वच्छता की सेवा ने पूरे देश को ऊर्जा से भर दिया है। पूरे देश में मन्त्रियों, सांसदों, केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, स्कूल, कालेजों, मशहूर हस्तियों, कॉर्पोरेट स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों गैर सरकारी संगठनों, छात्रों और नागरिक समाजिक संगठनों सभी ने बढ़कर श्रमदान किया जिससे पूरे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। एक मिसाल पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं वाराणसी के शहशाहपुर गाँव में एक ट्विन पिट शौचालय के निर्माण के लिए श्रमदान किया। स्वच्छता को निवेश से जोड़ा गया सबसे बड़ी बात कि इसे गंगा की वैदिक श्रेष्ठता तथा जनता के सभी वर्गों में शामिल किये जाया गया। स्वच्छता सम्बर्धन बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्या नहीं है बल्कि इसमें अधिक गहरी भूमिका व्यवहार सम्बन्धी एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में निभाती है।

60 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ऐसी चुनौती है, जिसका बीड़ा सम्भवतः दुनिया में कभी किसी ने नहीं उठाया है। जब सम्पूर्ण भारत ब्रिटिश गुलामी से त्राहि-माम कर रहा था। तभी पूरा देश महात्मा गांधी की आवाज के पीछे चल पड़ा और भारत ने स्वतन्त्र होकर दुनिया के सामने एक अहिंसात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जब देश सबसे ज्यादा खुले में शौच करने वाले देशों की कुख्यात सूची में बहुत ऊपर आ गया यह आंकड़ा कही न कही शक्ति अभिजन वर्ग के लिए एक चुनौती बन गया अतः तीन वर्ष पहले 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से राबडू को गंदगी से और खुले में शौच के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मुहिम की। साथ ही 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ और खिले में शौचमुक्त भारत बनाने का आह्वान 2 अक्टूबर 2019 को ही लक्ष्यपूर्ति तिथि बनाने का प्रमुख कारण यह था कि इस दिन महात्मा गांधी की 150 वी जयंती होगी जो कि स्वच्छता और हाइजीन के मुद्दे पर अपना ध्यान केन्द्रित करने वाले पहले महान नेता रहे साथ ही एक बार इन्होंने ही भारत के सम्पूर्ण जनमानस को स्वतन्त्रता प्राप्ति की मुहिम में अपने साथ खड़ा कर

लिया था। 2 अक्टूबर 2019 तक सभी जगह सफाई वास्तव में एक ऐसा विचार है। जिसका सही समय आ गया है, और इसके लिए जनता को ‘स्वच्छता’ को अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी आदत बनानी होगी यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक भारतीय ‘स्वच्छता सेवा’ शब्द के सादगर्भित रूप का नकारात्मक-सकारात्मक सभी पक्षों का आव्यमंथन करे तभी उसे वास्तव में यह एक नैतिक राजनैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी न महसूस होकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो मूल, भूत आवश्यकताओं में भी शामिल की जा सकती है का अनुभव होगा। खुले में शौच का भारतीय इतिहास बहुत पुराना है, मानव सभ्यता के आरम्भ से ही यह जन मानस की जीवन शैली का हिस्सा है एक के बाद एक सरकारें 1980 के दशक से ही राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन 2014 तक 39 प्रतिशत लोगो को ही सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएँ प्राप्त हो सकी। इसके गर्भ में जब हम जाते हैं, तो यह पता चलता है, कि लोगों में स्वच्छता जागरूकता की कमी है। जब तक लोगों को यह एक राजनैतिक तथ्य प्रतीत होगा तब तक ये इसे आत्मसात नहीं करेंगे और बिना आत्मसात किए 60 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ऐसी चुनौती है जिसका बीड़ा एक कल्पनालो से बढ़कर कुछ नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब तक भारतवासियों ने किसी मिशन को अपना नहीं समझा है तब तक सफलता नहीं मिली है चाहे वह सत्याग्रह द्वारा स्वतन्त्रता का आवाहन हो या शिक्षा अभियान।

स्वच्छता अभियान को यदि हम अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं तो यूनिसेफ के हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है, कि खुले में शौच से मुक्त गाँव में प्रत्येक परिवार चिकित्सा के खर्च, समय और जीवन रक्षा के लिहाज से हर वर्ष 50,000 रुपये बचा लेता है। इसके अलावा अच्छे ठोस तथा तरल संसाधन प्रबन्धन के जरिए कचरे से सम्पत्ति अर्जित करने की अचूक सम्भावना भी है। 10 वर्षों में स्वच्छता से हरेक परिवार को उस पर हुए कुल निवेश (सरकारी व्यय और घरेलू योगदान समेत खर्च के अन्य साधन) से 47 गुना आर्थिक लाभ हो जाते हैं। इससे स्वच्छता की सुविधाएँ बढ़ाने में निवेश की दलील को स्पष्ट रूप से काफी बल मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास पाँच वर्ष में 20 अरब डॉलर से अधिक का बजट है। निजी क्षेत्र, विकास एजेंसियों, या आस्था से सम्बन्धित संस्थाओं एवं नागरिकों से अतिरिक्त निवेश भी आ रहा है। स्वच्छ भारत कोष में पहले ही कुछ विशेष स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपये एकत्र एवं जारी किए जा चुके हैं। यह धनराशि व्यक्तियों, कम्पनियों एवं संस्थानों के निजी योगदान के जरिए इकट्ठी की गई है। ढेरों निजी कम्पनियों ने अपने सी0एस0आर0 कोष से विशेष रूप से स्कूलों के स्वच्छता के लिए काम किया है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के लिए निजी क्षेत्र की रचनात्मकता तथा नवाचार का फायदा उठाना तब तक बाकी रहेगा जब तक सभी भारतवासी स्वच्छता को व्यवहार में शामिल नहीं करेंगे। भारत सरकार के सभी मन्त्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने सफाई तथा स्वच्छता के

लिए अलग से बजट भी रखा है। यह मंजर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल मिलाकर 12000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन की गति तेज हो रही है। आज खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या घटकर 30 करोड़ के करीब हो गयी है और 68 प्रतिशत से भी अधिक भारतीयों को स्वच्छता के सुरक्षित साधन उपलब्ध है परन्तु अभी लम्बा रास्ता तय करना बाकी है, जिसमें सभी को अपनी कमर कसनी होगी और स्वच्छता का आत्ममंथन करके व्यवहार में लाना होगा। स्वच्छता ही सेवा, सर्वोदय-विकास से जोड़ने पर हमें स्वच्छता की जिम्मेदारी महसूस होती है गाँव का एक स्वच्छ व्यक्ति सभी ग्रामवासियों को स्वच्छता से परिचय कराता है जिससे धीरे-धीरे विकास का सम्राज्य दिखाई देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मन की बात के कुछ अंश (24 सितम्बर 2017) में जो संकल्प दिया वह कहीं न कहीं स्वच्छता के सारगर्भित रूप का ही परिप्रेक्ष्य प्रतीत होता है।

### स्वच्छता संकल्प (श्री नरेन्द्र मोदी)

- मेरे प्यारे देशवासियों पिछले महीने 'मन की बात' में ही हम सब ने एक संकल्प किया था और हमने तय किया था कि गांधी जयंती से पहले 15 दिन देशभर में स्वच्छता उत्सव मनायेंगे।
- हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस कार्य का उद्घाटन किया (राष्ट्रपति कोविन्द उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के इश्वरीगंज गाँव से 15 सितम्बर 2017 को स्वच्छता की सेवा का आरम्भ किया) बालक, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी गाँव से जुड़ गये।
- 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' के सिर्फ 4 दिन में ही करीब 75 लाख से ज्यादा लोगो ने मीडिया की पहल को कहा आभार है जो इन्होंने अपने अपने तरीके से सकारात्मक वातावरण बनाया।
- अक्टूबर माह में अनेक महापुरुषों का जन्म दिवस है, गांधी से लेकर पटेल तक इनके जीवन का उपदेश देश के लिए कुछ करना था न की मात्र कहना। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में शहशाहपुर गाँव में दोहरे गढ़े वाले शौचालय में निर्माण के लिए श्रमदान किया तथा गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लेने वाले से बातचीत की। श्री मोदी ने शौचालय को 'इज्जत घर' नाम दिए जाने के पहल की सराहना की। साथ ही कहा कि "स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है" इस भावना को हम सभी को स्वयं विकसित करने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन (एस0बी0एम0) शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छ मन्त्रालय का संयुक्त मिशन है। देश को अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। आज वह शुरुआत एक जनआन्दोलन के रूप में दिखाया दे रहा है। देश के मुखिया द्वारा स्वच्छता का बिगुल बजाना इस मुद्दे को विश्व स्तर पर पहुँचाने में कारगर रहा। विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है, कि गंदगी के कारण भारत के लगभग 40% बच्चे

का शारीरिक मानसिक विकास बधित होता है। इसका उनकी आर्थिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक है। हर साल संक्रमण से एक लाख लोगों से अधिक बच्चों की मौत होती है। अतः प्रधानमंत्री ने इसे महसूस करके सकारात्मक कार्य किए जाने की आवश्यकता का अनुभव किया। एस0बी0एम0 विश्व स्तर पर एक अनुठा कार्यक्रम है, जो दुनिया में स्वच्छता की किसी भी अन्य पहल से बहुत भिन्न है व्यापकता और स्तर दोनों के लिहाज से आज का स्वच्छता अभियान अनेक स्तरों पर अधिक भिन्न और व्यापक है- आज के इस अभियान में (1) सूचना शिक्षा और संचार (आई0ई0जी0) के माध्यम से आचरण में परिवर्तन पर वास्तव में ध्यान केन्द्रित किये जा रहा है।

(2) आउटपुट की अपेक्षा आऊट कम पर ध्यान दिया जा रहा है।

(3) इस पूरी प्रक्रिया के सम्पादन में न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरा समुदाय संलिप्त है।

(4) बच्चे, महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक और युवा सभी स्वच्छता चैम्पियन के रूप में उभरे हैं।

(5) स्वच्छता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यकर्ताओं को स्वच्छाग्रही कहते हैं इन स्वच्छाग्रही को समुदायिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(6) पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्चुअल क्लासरूम का संचालन किया जा रहा है। बालीवुड सितारे से लेकर लगभग सभी लोग यथायोग्य जागरूकता में भाग ले रहे हैं। मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पूर्ण सहयोग कर रहा है।

भारत के राष्ट्रपति ने 15 सितम्बर 2017 को 'स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार और स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि' पुरस्कार देकर इस पखवाड़े का समापन किया। स्वच्छ भारत मिशन को ना सिर्फ फाइलों में लागू करने की पहल हुई बल्कि इसकी वास्तविक रूप में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्प्रेषण नीति द्वारा भारत की विशाल आबादी के व्यवहार परिवर्तन में कोशिश की गयी जो सफल भी हुई। मिशन को सफल बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि, एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाये जो जन-समुदायों को प्रतिभागी प्रविधियों से अधिकार सम्पन्न बनाए ताकि लोग स्वयं सोच समझ कर स्वच्छता के मुद्दों पर फैसले लें। 2011 की जनगणना में जब यह बात सामने आयी कुल आबादी का 68.84% आबादी गाँव में रहता है, और दो तिहाई आबादी शौचालय की सुविधा से वांचित है। यह एक चौकाने वाला आकड़ा था साथ ही विकास की बात करने वाले शासकों प्रशासकों पर एक प्रश्न चिन्ह भी था। 2011 की जनगणना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गाँव की दृष्टि में शौचालय गौण आवश्यकता है। अतः स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में प्रमुख समस्या जनता का दृष्टिकोण था जिसे परिवर्तित करना एक चुनौती थी। इस चुनौती को जीतने के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम हुए जिसमें सबसे प्रमुख 'स्वच्छायॉन 1.0' योजना का आयोजन किया

गया जिसका उद्देश्य स्वच्छता से सम्बन्धित मुद्दों पर जनता को समाधान प्राप्त कराना था तथा शौचालय को विशिष्ट तकनीक से जोड़ना था। स्वच्छायॉन के प्रमुख लक्ष्य में अभिनव समाधान को लागू किया गया था।

1. पर्वतीय शुष्क बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में अनुकूल टेक्नोलॉजी वाले शौचालय की व्यवस्था।
2. साफ सफाई और उपयोग के सम्बन्ध में व्यवहार परिवर्तन के लिए तकनीकी समाधान।
3. स्कूलों के शौचालय के संचालन और रख रखाव में सुधार के लिए अभिनव विधियों तथा मॉडल।
4. महिलाओं में माहवारी के दौरान स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अभिनव समाधान।
5. मानव मल को जल्द सड़ने के लिए अभिनव समाधान।

स्वच्छायॉन 1.0 के अन्तर्गत इन पाँच लक्ष्यों को पूरा करने का सतत प्रयास किया गया है। यह सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों सभी आयु वर्गों एवं सामुहिक/व्यक्तिगत भागीदारी के लिए खुला था। 2 अगस्त 2017 को सभी नागरिकों से सम्बन्धित श्रेणियों में अपनी अपनी प्रविष्टियाँ माईगॉव पोर्टल के जरिए भेजने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया, चर्चित हस्तियों प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए स्वच्छायॉन का प्रचार किया गया। राज्य सरकारों ने सम्भावित भागीदारी तक पहुँचने के लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सक्रिय प्रतिभागिता की तथा प्रविष्टी जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2017 रखी। स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे प्रशासकीय क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली एक विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में सेमीफाइनल के लिए प्रविष्टियों का चयन किया। 57 चयनित प्रतिभागियों को 7 सितम्बर 2017 से शुरू होने वाले दूसरे दौर के लिए दिल्ली बुलाया गया जहाँ उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों वाली एक बाहरी निर्णायक समिति के सामने अपने विचारों/समाधानों के नमूने पेश किए। इस दौर की शुरुआत नीति आयोग द्वारा नवोन्मेष तथा आरम्भिक सहायता के सत्र के साथ हुई। मूल्यांकन में पेशेवर तथा क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल थे। प्रतिभागी का मूल्यांकन उनके समाधान की नवीनता, उपयोगिता, किफायत, रखरखाव में आसानी, टिकाऊपन, बड़े स्तर पर प्रयोग की क्षमता तथा पर्यावरण सम्बन्धी अनुकूलता के आधार पर किया गया। अन्तिम सूची में चूने गए प्रतिभागियों को विशेषज्ञों की बड़ी निर्णायक समिति के सामने अपने नमूने/रणनीति के साथ छोटी सी प्रस्तुति देनी थी। प्रत्येक श्रेणी में विजेता को चुना गया और 3 लाख रुपये इनाम दिए गये। इसी

प्रस्तुतीकरण में कुछ अनूठी पेशकश भी दिखायी दी जैसे जन स्वास्थ्य इंजनियरिंग विभाग (पी0एच0ई0डी0) के श्री राम प्रकाश तिवारी ने एक तकनीक पेश की, जिसमें दो गड्ढों वाले शौचालय की तकनीक में ईटों के बजाय प्लास्टिक की परत के साथ बांस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश जैसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ मोटर वाहन चलने लायक सड़के कम हैं, में उपयोगी होगा। शौचालय बनाने में यहा राजमिस्त्री एवं कच्चा माल असम से आता है। जिससे लागत बढ़ जाती है इस अभिनव उपयोग से अरुणाचल में स्थानीय सामग्री तथा स्थानीय लोगो के हुनर का प्रयोग होगा और शौचालय निर्माण सस्ता तथा टिकाऊ भी रहेगा। मासिक धर्म से सम्बन्धित कचरे के निस्तारण के लिए केरल से ऐश्वर्या ने सैनिटरी पैडों में रसायन का इस्तेमाल किया और अवशिष्ट से उर्वरकों एवं पौधे रखने की थैलियों के रूप में प्रयोग किया।

### निष्कर्ष

स्वच्छता अभियान की शुरुआत भले ही महात्मा गांधी के समय से ही हो गयी थी परन्तु वास्तविक क्रियाशीलता, कानून, अभिनव तकनीकी, संकल्प प्राप्ति की ललक अब प्रारम्भ हुई है परन्तु यह पुनः ठण्डे बस्ते में न चली जाये इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भारत के जनमानस की है। स्वच्छता को आत्मा से आत्मसात करने का प्रयास करे। इसे एक व्यक्तिगत सेवा धर्म समझें तभी स्वच्छता के लिए बने सभी नियमों कानूनों सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा तथा विश्व समाज के समक्ष गौरवान्वित महसूस करेंगे।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संपादकीय ललित खुराना अक्टूबर 2017।
2. दूरदर्शन चैनल का सीधा प्रसारण 15 अगस्त 2014।
3. सम्पादकीय लेखक अरुण जेटली केन्द्रीय वित्त एवं कंपनी मामलों के मन्त्री।
4. कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2017 अंक 12
5. सीधा प्रसारण दूरदर्शन 'मन की बात' 24 सितम्बर 2017
6. भारत 2017 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार पृष्ठ 668
7. संपादकीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय सचिव परमेश्वरन अय्यर
8. पद्मकांत झा का सम्पादकीय लेख (नीति आयोग के उप सलाहकार)
9. पेयजल स्वच्छता टीम में शामिल रेनी बिल्फ्रेड का सम्पादकीय लेख कुरुक्षेत्र।